- 20th Year
- Issue: 132
- 15.09.2026 (TUESDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

ब्रिक्स में भारत की शानदार कूटनीतिक सफलता ने ब्रांड मोदी को और मजबूत किया

नयी दिल्ली १४/०९ (संवाददाता): दिल्ली में हुई ब्रिज़्स शिखर बैठक को अगर केवल एक अंतरराष्ट्रीय सज़्मेलन मानकर देखा जाएगा तो उसकी असली राजनीतिक अहमियत समझ में नहीं आएगी। देखा जाये तो यह बैठक ऐसे समय में हुई, जब दुनिया कई मोर्चों पर तनाव, युद्ध, अविश्वास और बदलते शक्ति-संतुलन से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत ने जिस तरह अलग-अलग ध्रुवों के देशों को एक मंच पर बैठाया, संवाद के रास्ते खोले और मतभेदों के बावजूद सहयोग की जमीन तैयार की, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलज़्धि के तौर पर सामने आई है। ब्रिज़्स की इस बैठक की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि भारत ने उन देशों के बीच भी संवाद की संभावना पैदा की, जिनके बीच गहरे मतभेद हैं। ईरान और खाड़ी के देशों के बीच बातचीत इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। पश्चिम एशिया लंबे समय से टकराव, अविश्वास और संघर्ष का मैदान बना हुआ है। ऐसे समय में दिल्ली का मंच बातचीत के लिए उपलज़्ध होना अपने आप में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाया कि भारत किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि अलग-अलग पक्षों से संवाद करते हुए अपने लिए स्वतंत्र कूटनीतिक स्थान बना सकता है। भारत और चीन के बीच हुई बातचीत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सीमा विवाद और लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बावजूद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व का आमने-सामने बैठना इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना संवाद के दरवाजे बंद नहीं करता। यही वह बिंदु है जहां मोदी की कूटनीति की ताकत दिखाई देती है। अमेरिका से संबंध भी कायम हैं, रूस के साथ रिश्ते भी बने हुए हैं, चीन से संवाद भी हो रहा है और पश्चिम एशिया के अलग-अलग देशों के साथ भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। यानी भारत किसी एक शक्ति के पीछे चलने के बजाय अपनी शर्तों पर संबंधों का संतुलन साध रहा है। यही सफलता उस राजनीतिक नैरेटिव को भी कमजोर करती है, जिसमें बार-बार यह सवाल उठाया जाता रहा कि अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने मक्का समझौता कर लिया, दूसरे देशों के साथ अपने समीकरण बना लिए और क्षेत्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ गतिविधियां बढ़ीं तो ज़्या भारत

की विदेश नीति असफल हो गई? विदेश नीति को केवल पड़ोस की तत्काल घटनाओं से मापना वास्तविक तस्वीर को छोटा कर देना है। असली सवाल यह है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत को किस नजर से देख रही हैं और संकट के समय कितने देश भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। दिल्ली की बैठक ने इस सवाल का जवाब काफी हद तक दे दिया है। यहां प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीतिक छवि भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी चिनफिंग की तस्वीरें जिस तरह वैश्विक स्तर पर चर्चा में आई हैं, उनका राजनीतिक संदेश तस्वीर से कहीं बड़ा है। यह तस्वीर बताती है कि भारत का नेतृत्व एक साथ दुनिया की अलग-अलग शक्तियों के साथ संवाद करने की स्थिति में है। पश्चिमी देशों के लिए भी यह संदेश महत्वपूर्ण है कि भारत को नजरअंदाज करके वैश्विक राजनीति की कोई बड़ी रणनीति पूरी नहीं हो सकती। इसका घरेलू राजनीतिक असर भी कम नहीं होगा। भाजपा लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत वैश्विक छवि को अपनी राजनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल करती रही है। ब्रिज़्स की दिल्ली बैठक उस पूंजी को और मजबूत करने का अवसर देती है। विपक्ष यदि यह कहता है कि सरकार की विदेश नीति कमजोर पड़ गई है, तो भाजपा के पास दिल्ली में जुटे वैश्विक नेताओं, भारत की मध्यस्थ भूमिका और अलग-अलग शक्ति केंद्रों के साथ संवाद को सामने रखने का मजबूत राजनीतिक आधार तैयार हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मिली यह कूटनीतिक सफलता केवल एक शिखर सज़्मेलन की सफलता बनकर नहीं रहने वाली। इसका सीधा और दीर्घकालिक लाभ भारत की सामरिक स्थिति को मिल सकता है। रूस, चीन, अमेरिका, यूरोप, ईरान और खाड़ी देशों जैसे अलग-अलग शक्ति केंद्रों के साथ एक साथ संवाद कायम रखने की मोदी की क्षमता ने यह संदेश दिया है कि भारत किसी दबाव या धड़े की राजनीति में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ संबंध तय करने की स्थिति में है। इसका असर आने वाले समय में व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक सहयोग और भारत की वैश्विक हैसियत, हर मोर्चे पर दिखाई दे सकता है। साथ ही इस सफलता का एक घरेलू राजनीतिक पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा इस उपलज़्धि को प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रमाण के रूप में जनता के सामने रख सकती है। विपक्ष यदि विदेश नीति को लेकर सरकार पर सवाल उठाता है, तो भाजपा के पास दिल्ली में एक साथ जुटे विश्व के बड़े नेताओं और मोदी की सक्रिय कूटनीतिक भूमिका को सामने रखने का अवसर होगा। यानी ब्रिज़्स की सफलता सिर्फ दिल्ली की कूटनीतिक मेज पर मोदी की जीत नहीं है; यह आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार और मोदी की नेतृत्व छवि को और मजबूत करने वाली उपलज़्धि भी बन सकती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन की सफलता ने घरेलू राजनीति में ब्रांड मोदी को और मजबूत कर दिया है।

राहुल गांधी के एमपी दौरे से पहले सक्रिय हुई भाजपा, १७ सितंबर को उज्जैन पहुंचेंगे नितिन नबीन

नयी दिल्ली १४/०९ (संवाददाता): लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित मध्यप्रदेश दौरे को लेकर छात्रों के मुद्दों पर राज्य की सियासत में एक बार फिर टकराव के आसार बन गए हैं। राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर में 'छात्रों की गूंज' को संबोधित करने वाले हैं। इससे दो दिन पहले 17 सितंबर को नवीन का मध्यप्रदेश दौरा प्रस्तावित है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष के उज्जैन, मंदसौर या इंदौर में युवाओं के साथ बातचीत करने की उज़्मीद है। हालांकि, पार्टी ने अभी तक उनके विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।

भाजपा की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोमवार को यहां भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, "नितिन नवीन की उज्जैन यात्रा 17 सितंबर को प्रस्तावित है। इसे आज अंतिम रूप दिया जाएगा। उसके बाद, हम आपको उनके

कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।" उन्होंने कहा कि नवीन का उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर जाने का कार्यक्रम है।

खंडेलवाल ने कहा, "कार्यक्रम की योजना अंतिम चरण में है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद, हम आप सभी के साथ विस्तृत कार्यक्रम साझा करेंगे।" राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भाजपा ने शुरुआत में राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम को हल्के में लिया था। वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य ने कहा, "अब जब इसकी गंभीरता को उन्होंने समझा है तब जाकर आनन-फानन में नवीन की मध्यप्रदेश दौरे की योजना बनायी जा रही है। मालवा, जिसमें इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और अन्य जिले शामिल हैं, भाजपा का गढ़ रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस ने राहुल की यात्रा के लिए इस क्षेत्र को चुना है।"

उन्होंने दावा किया कि 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर बड़ी संज़्या में 'फॉलोअर्स' वाली दो प्रमुख हस्तियों के भी राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने की उज़्मीद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्यप्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर से मालवा में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जहां आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान हैं और देश भर के छात्र यहां पढ़ने आते हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को 'छात्रों की गूंज' को एक गैर-राजनीतिक कार्यक्रम बताया था। कांग्रेस ने शुरुआत में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के आयोजन के लिए शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की अनुमति मांगी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के बाद कार्यक्रम की तारीख 12 सितंबर से बदलकर 19 सितंबर कर दी गई।

केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन के बाद एसडीआरएफ ने ६५०० तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला

नयी दिल्ली १४/०९ (संवाददाता): चीड़वासा हेलीपैड के समीप भूस्खलन व केदारनाथ पैदल मार्ग के बाधित होने से फंसे 6500 से अधिक तीर्थयात्रियों को सोमवार को बचाव एवं राहत दलों की देखरेख में सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) से मिली जानकारी के अनुसार, गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन से उसके आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन के समन्वय से यात्रियों को सुरक्षित रूप से रास्ता पार कराया।

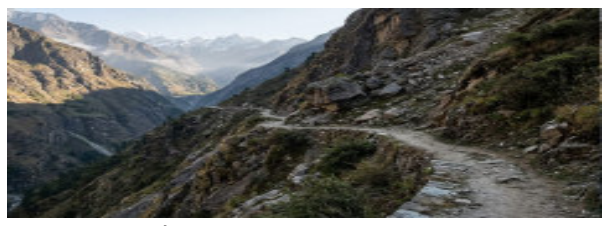

एसडीआरएफ के मुताबिक, अब तक 6500 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। साथ ही करीब 600-700 घोड़े-खच्चरों को भी सुरक्षित निकाला जा चुका है। गौरीकुंड से लगभग ढाई किलोमीटर ऊपर चीड़वासा हेलीपेड के समीप रविवार को पहाड़ी से चट्टान और पत्थर गिरने के कारण मार्ग अवरूद्ध हो गया था। भूस्खलन के दौरान चट्टानों की चपेट में आने से एक स्थानीय निवासी की मौत हो गयी थी। पुलिस के मुताबिक भूस्खलन के बाद पैदल मार्ग पर आवाजाही रोक दी गयी थी। उसने बताया कि पहाड़ी से निरंतर पत्थर गिरने के कारण मार्ग पर से मलबा हटाने में भी दिक्कतें आ रही थीं जिस कारण तीर्थयात्रियों को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के दोनों तरफ सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न पड़ावों पर रोक दिया गया था। सोमवार सुबह मौसम अनुकूल होने और चट्टानों व पत्थरों के गिरने का सिलसिला थमने के बाद केदारनाथ से लौटने वाले श्रद्धालुओं को बाधित क्षेत्र से बचाव दलों की देखरेख में चरणबद्ध ढंग से सुरक्षित निकाला गया।

कोलकाता में सुवेंदु अधिकारी ने वाम दलों पर साधा निशाना

कोलकाता १४/०९ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल के मुज़्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को लोगों से "असुरों और राष्ट्रविरोधी ताकतों" से सतर्क रहने का आग्रह किया। उनका इशारा परोक्ष तौर पर वाम दलों की ओर था। शुभेंदु

अधिकारी ने सात्विक संस्कृति की रक्षा करने का भी आह्वान किया और दावा किया कि मई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सज़ा में आने के बाद इसे राज्य में "फिर से स्थापित" किया गया है। मुज़्यमंत्री अधिकारी ने ये टिप्पणियां शहर में गणेश प्रतिमा की स्थापना के दौरान कीं। उन्होंने कहा, "सुबह से मुझे गणेश पूजा मनाने और पूजा शज़्द का इस्तेमाल करने को लेकर मुज़्य रूप से वामपंथियों की ओर से काफी अपशज़्द मिल रहे हैं। मैं वाम दलों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि विश्वकर्मा पूजा के दिन मैं (राज्य सचिवालय) नबान्न में पुष्पांजलि दूंगा।आइए, मेरे साथ शामिल हों।" मुज़्यमंत्री दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के बाहर वाम दलों द्वारा लगाए जाने वाले बुक स्टॉल पर "शरदोत्सव" लिखे जाने और "दुर्गा पूजा" शज़्द का इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर लगातार वाम दलों पर निशाना साधते रहे हैं।

ब्रिक्स को बड़ी उपलब्धि बताया कपिल सिब्बल ने, बांधे तारीफों के पुल

नयी दिल्ली १४/०९ (संवाददाता): राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिज़्बल ने सोमवार को कहा कि नई दिल्ली में हाल ही में हुए ब्रिज़्स समेलन से चीन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने इस समूह को अलग-अलग तरह के देशों का एक मिला-जुला समूह बताया, जिससे ठोस फ़ैसले निकलना मुश्किल था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिज़्बल ने कहा कि अध्यक्ष के तौर पर भारत को सदस्य देशों के बीच मतभेदों को संभालते हुए एक संयुक्त घोषणा-पत्र तैयार करना पड़ा। उन्होंने कहा हमारे लिए यह होर्मुज़ (जलडमरूमध्य) से गुज़रने जैसा था। चीन और रूस इसे पश्चिमी देशों के विरोध वाले एक वैकल्पिक गुट के तौर पर बनाना चाहते हैं और ऋह्लष्ट (रूस, भारत, चीन) अब

असल में रूस, ईरान और चीन बन गया है... हम नहीं चाहेंगे कि यह (पश्चिमी देशों के विरोध वाला गुट) बने। सिज़्बल ने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र में किसी वैकल्पिक मुद्रा या डी-डॉलरलाइजे़शन की बात नहीं की गई, और इसे भारत के लिए एक उपलज़्धि बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद पर समूह का रुख़ बदलती वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा लेकिन हमें, और दुनिया के अन्य देशों को भी, यह पता चल गया है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध नहीं जीतेगा। यह हमारे प्रस्ताव में भी झलका, ज़्योंकि उसमें फ़िलिस्तीन और दो-राष्ट्र सिद्धांत की बात की गई थी। ब्रिज़्स को देशों का एक विविध समूह बताते हुए सिज़्बल ने कहा कि यह एक उल्लेखनीय उपलज़्धि है कि सदस्यों ने बिना किसी विवाद के एक संयुक्त बयान अपनाया। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारी सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलज़्धि है कि बिना किसी विवाद के एक संयुक्त प्रस्ताव पारित हो गया। निर्दलीय राज्यसभा सांसद ने कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई गैर-पश्चिमी गठबंधन नहीं हो सकता। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को हुआ है। हालांकि, सिज़्बल ने सवाल उठाया कि ज़्या घोषणापत्र में किए गए वादे असल में लागू होंगे या नहीं; उन्होंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर इनका कार्यान्वयन होगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। रविवार को नई दिल्ली में ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें सदस्य देशों ने एक घोषणापत्र अपनाया। इस घोषणापत्र में वैश्विक शासन और व्यापार प्रणाली में सुधार की मांग की गई। समूह ने लॉजिस्टिज़्स और सप्लाई चेन, स्टार्टअप्स तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम से जुड़े नतीजों की भी घोषणा की।

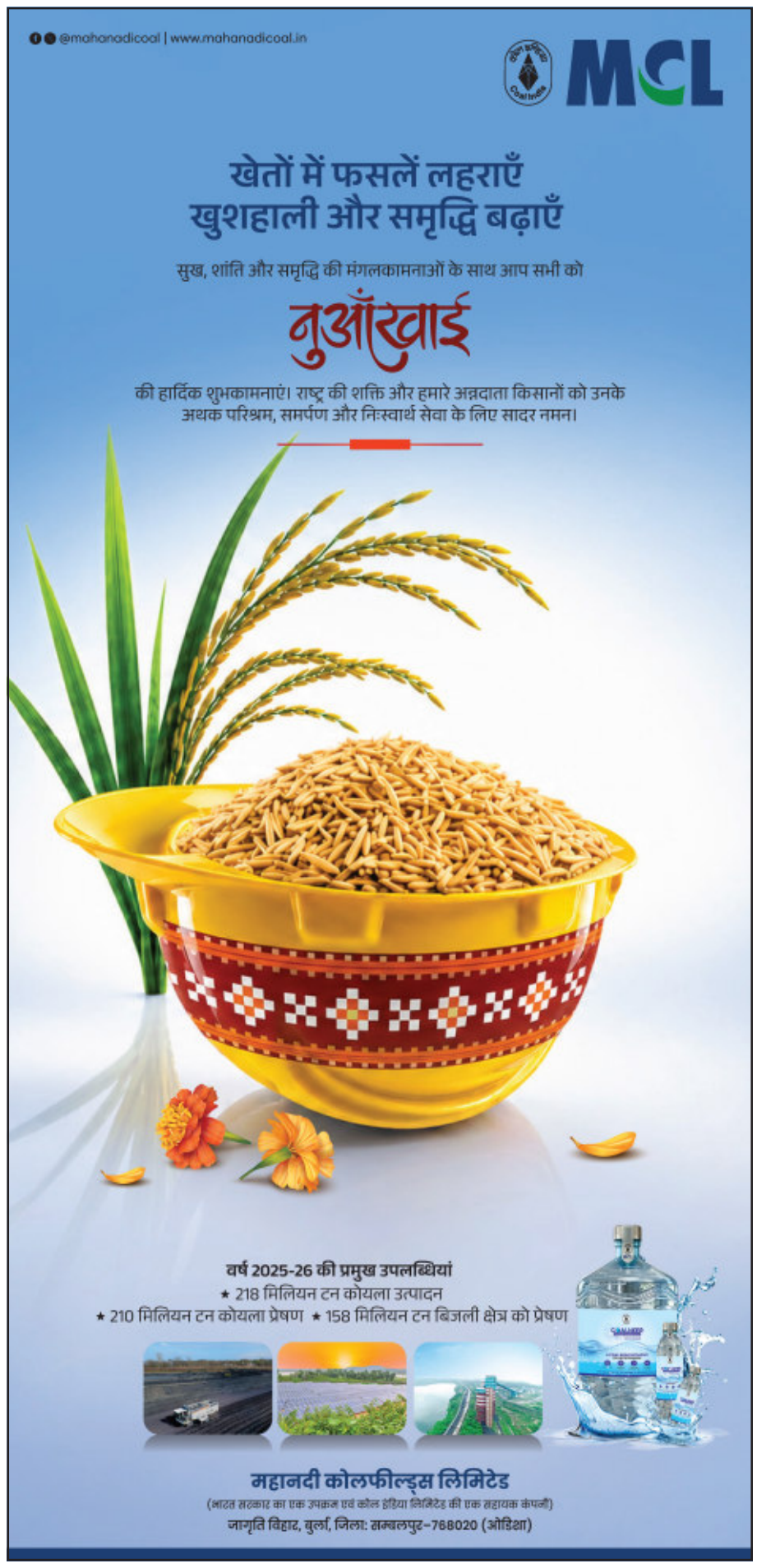

विविध समाचार

ब्रिज़्स शिखर समेलन के साझा घोषणापत्र भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, विशेषज्ञों ने सराहा

नयी दिल्ली १४/०९ (संवाददाता): सामरिक मामलों के कई विशेषज्ञों ने ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन के साझा घोषणापत्र को सोमवार को भारत के लिए एक कूटनीतिक सफलता बताया जबकि कुछ जानकारों ने ब्रिज़्स के रुख को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत के आह्वान का समर्थन करार दिया। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि पिछले साल जज़्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की ब्रिज़्स नेताओं द्वारा कड़े शज़्दों में निंदा किए जाने से नयी दिल्ली घोषणापत्र भारत के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ईरान के बीच गहरे मतभेदों को दूर करने के बाद समूह ने 12 सितंबर को सर्वसज़्मति से साझा घोषणापत्र जारी किया, जिसमें ईरान पर अमेरिकी हमलों के लिए अमेरिका का सीधा उल्लेख नहीं किया गया। पर्यटनस्थल खोजें

घोषणापत्र के मसौदे पर बातचीत अंतिम समय तक चली ज़्योंकि शुरुआत में ईरान और यूएई दोनों ने कड़ा रुख अपनाया था। साल 2003 से 2006 तक बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रहीं वीणा सीकरी ने इस घोषणापत्र को भारत के लिए एक जबरदस्त कूटनीतिक सफलता बताया। उन्होंने कहा, अब कोई अगर-मगर नहीं है।

दुनिया के शीर्ष मंच पर आज भारत का प्रभाव है। यह बड़ी सफलता मुज़्य रूप से (भारतीय) प्रधानमंत्री की (ईरानी) राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबू धाबी के युवराज (शेख खालिद बिन मोहज़्मद) के साथ हुईं द्विपक्षीय बैठकों का परिणाम है। निश्चित रूप से शेरपा, राजदूत सुधाकर दलेला और मंत्री के नेतृत्व वाली पूरी टीम ने मेहनत की और 24 घंटे काम किया।

वे एक मसौदे पर सहमति बनाने के लिए तड़के 3-4 बजे तक सभी से बात कर रहे थे। सीकरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की पृष्ठभूमि को देखते हुए दिल्ली में अबू धाबी के युवराज और ईरानी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक भी महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और ब्रिज़्स के अन्य सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में पहले दिन के विचार-विमर्श के बाद घोषणापत्र को स्वीकार करने की घोषणा की थी।

सीकरी ने कहा कि नयी दिल्ली घोषणापत्र का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है ज़्योंकि भारत ने

हमेशा यह माना और कहा है कि ब्रिज़्स एक गैर-पश्चिमी समूह है, लेकिन यह पश्चिम-विरोधी समूह नहीं है , और यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई है। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने 'एज़्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन ने एक विखंडित होती दुनिया में भारत की हैसियत की एक महत्वपूर्ण तस्वीर पेश की। उन्होंने लिखा, भारत गैर पश्चिमी देशों के इस समूह को स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन इसे (ब्रिज़्स) स्पष्ट रूप से पश्चिम-विरोधी बनने देने में भारत को बहुत फायदा नहीं दिखता।

भारत का उद्देश्य बिना किसी टकराव के चीजें बेहतर बनाना है। भारत चाहता है कि पश्चिमी देशों के बाज़ारों, उनकी पूंजी और प्रौद्योगिकी से दूरी बनाए बगैर एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था बने, ग्लोबल साउथ को अधिक अधिकार मिलें और आर्थिक दबाव से सुरक्षा मिले।卐 राव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर इस अंतर को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिज़्स किसी के खिलाफ नहीं है।卐 उन्होंने कहा कि भारत ने इस शिखर सज़्मेलन को अमेरिका विरोधी बयानबाजी का मंच बनाने के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने कहा, किसी साझा ब्रिज़्स मुद्रा का समर्थन या डॉलर पर निर्भरता खत्म करने की कोई नाटकीय घोषणा नहीं हुई।

ध्यान राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान, विभिन्न देशों के बीच तेजी से भुगतान, सुविधाजनक आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, भोजन व ऊर्जा सुरक्षा, और संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ व विश्व बैंक के सुधार पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया को लेकर ईरान और यूएई के बीच भारी मतभेदों के बावजूद भारत ने सर्वसज़्मति से नयी दिल्ली घोषणापत्र जारी करने में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता हासिल की। सावधानीपूर्वक तैयार किए गए घोषणापत्र के माध्यम से आम सहमति बनाए रखी गई। ब्रिज़्स नेताओं ने घोषणापत्र में पश्चिम एशिया संघर्ष के संदर्भ में अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कार्यों से बचने का आह्वान किया है, जिनसे स्थिति और बिगड़ने की आशंका हो। भारत ने हमेशा कहा है कि किसी भी संघर्ष को सुलझाने का रास्ता संवाद और कूटनीति ही है। यूनेस्को में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी. शर्मा ने इस साझा घोषणापत्र को दुनिया भर में भारत के मजबूत नेतृत्व के प्रति समर्थन करार दिया। उन्होंने कहा कि शिखर सज़्मेलन से पहले 30 भारतीय शहरों में 400 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। शर्मा ने पेरिस से फोन पर 'पीटीआई-भाषा' से बात करते हुए कहा, ब्रिज़्स भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया समूह है, जिसका उद्देश्य है कि दुनिया बहुध्रुवीय बने, जिसमें मजबूत साझेदारियां हों। इसलिए मुझे लगता है कि यह (घोषणापत्र) दुनिया भर में भारत के नेतृत्व के प्रति एक बड़ी स्वीकार्यता है। उन्होंने आतंकवाद पर ब्रिज़्स के रुख और पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा किए जाने की भी सराहना की।

ब्रिज़्स देशों ने घोषणापत्र में आतंकवाद के किसी भी रूप को कतई बर्दाश्त नहीं करने और इस खतरे से निपटने में दोहरे मानदंडों को खत्म करने के भारत के आह्वान का पूरी तरह से समर्थन किया। समूह के शीर्ष नेता इस चुनौती से निपटने के लिए एक ठोस दृष्टिकोण रखने पर सहमत हुए।

ब्रिज़्स इंडिया समिट 2026 की सफलता पर बोले एस जयशंकर, बंटी दुनिया में भारत ने बनाई सहमति

१४/०९ (संवाददाता): विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ब्रिज़्स इंडिया समिट 2026 के सफल समापन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की मजबूत एकजुट करने की क्षमता को दिखाया और यह साबित किया कि बहुत ज़्यादा बंटी हुई दुनिया में भी आम सहमति बनाई जा सकती है। मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने बताया कि समिट में 32 प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया, जिनमें 11 सदस्य देशों, 10 सहयोगी देशों, चार क्षेत्रीय संगठनों और सात अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर देशों का प्रतिनिधित्व सबसे ऊँचे स्तर पर किया गया; इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल

रामफोसा, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली, मिस्र के राष्ट्रपति अज़्देल फतह अल-सीसी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहज़्मद बिन ज़ायद अल नाहयान की मौजूदगी खास रही।

जयशंकर ने कहा कि सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है, वह है मोदी के भारत की लोगों को एक साथ लाने की मज़बूत क्षमता; ज़्यादातर देशों का प्रतिनिधित्व राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख स्तर पर किया गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की भागीदारी पर भी ज़ोर दिया और कहा कि इस शिखर सज़्मेलन ने नेताओं को 卐बहुत खुली और सहज बातचीत卐 करने का मौका दिया। जयशंकर ने कहा कि यह शिखर सज़्मेलन एक बहुत बंटी हुई दुनिया के माहौल में हुआ, जिसमें बड़े संघर्ष और गहरे मतभेद थे, लेकिन भारत कुछ सबसे मुश्किल मुद्दों पर आम सहमति बनाने में सफल रहा। उन्होंने कहा हमने जो किया, वह यह था कि इस बंटवारे के बावजूद हमने आम सहमति बनाई, उन्होंने खास तौर पर पश्चिम एशिया के संघर्ष का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि ब्रिज़्स (क्लस्टर) नेता शांति, सुरक्षा, स्थिरता और लंबे समय तक चलने वाली समझ की ज़रूरत पर सहमत हुए, साथ ही उन्होंने वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और ऊर्जा के सुचारू प्रवाह के साथ-साथ नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर भी ज़ोर दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि शिखर सज़्मेलन का एजेंडा अर्थव्यवस्था, विकास और तकनीक पर केंद्रित रहा, जिसमें %ग्लोबल साउथ% (विकासशील देशों) का पक्ष लेने पर खास ज़ोर दिया गया। उन्होंने कहा एजेंडा अर्थव्यवस्था, विकास, तकनीक और %ग्लोबल साउथ% के लिए था - ग्लोबल साउथ% का साथ देने पर केंद्रित था। यह एक बहुत मज़बूत संदेश था जो सामने आया।जयशंकर ने कहा कि समिट के दो मुज़्य सेशन जो सुधार और मज़बूती पर केंद्रित थे, ऐसे विषय थे जिन्होंने अलग-अलग राय रखने वाले देशों को एक साथ लाने में मदद की। विदेश मंत्री ने आतंकवाद पर बनी आम सहमति का भी ज़िक्र किया और कहा कि ब्रिज़्स ने साफ़ कर दिया है कि आतंकवाद अपने किसी भी रूप या तरीके में मंज़ूर नहीं है। उन्होंने %नई दिल्ली घोषणापत्र% में 22 अप्रैल, 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा और आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाने और इस खतरे से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने की बात पर ज़ोर दिया।

रास सीट न मिलने पर छलका आनंद शर्मा का दर्द, बोले-आत्मसम्मान की कीमत चुकानी पड़ती है

नयी दिल्ली १४/०९ (संवाददाता): कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने गुरुवार को कहा कि राजनीति में आत्मसज़्मान बहुत महंगा होता है और सच बोलना अब अपराध माना जाता है। यह बयान उन्होंने तब दिया जब पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुराग शर्मा को अपना उज़्मीदवार नामित किया। दिल्ली रवाना होने से पहले शिमला में एएनआई से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्हें पार्टी उज़्मीदवार के रूप में ज़्यों नहीं चुना गया, इस पर टिप्पणी करने की उनकी कोई संभावना नहीं है।

आनंद शर्मा ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं निराश हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा- राजनीति में आत्मसज़्मान बहुत महंगा होता है। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और सच बोलना अब अपराध माना जाता है। पार्टी

नेतृत्व के फैसले का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि इसका जवाब केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यों नहीं भेजा गया और आखिरी समय में उज़्मीदवारी वापस ज़्यों ली गई, इसका जवाब केवल वही लोग दे सकते हैं जो फैसले लेते हैं और जिनकी सलाह पर फैसले लिए जाते हैं। इस पर टिप्पणी करने की मेरी कोई संभावना नहीं है।

शर्मा ने कहा कि जो कुछ हुआ है, उससे मैं डरता नहीं हूँ। निर्णय लेने वालों के पास सर्वोच्च कमान का अधिकार है। शायद उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से यह निर्णय लिया है। वे इसके गुण-दोषों को समझा सकते हैं। जो कुछ हुआ है, मैं उसे समझा नहीं सकता। जब उनसे पूछा गया कि ज़्या यह निर्णय पार्टी नेतृत्व की सिफारिश पर लिया गया था, तो शर्मा ने कहा कि वर्षों से हिमाचल प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सौभाग्य की बात रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शिमला

गढ़चिरौली मुठभेड़! 24 घंटे से जारी जंग में एक नज़्सली ढेर, सी-60 कमांडो घायल

गढ़चिरौली १४/०९ (संवाददाता):महाराष्ट्र के घने और दुर्गम जंगलों में देश की सुरक्षा के लिए तैनात सी-60 कमांडो और सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपने अदज़्य साहस और बेजोड़ रणनीति का लोहा मनवाया है।

अपनी जान हथेली पर रखकर नज़्सलियों के गढ़ में घुसने वाले इन जांबाज जवानों ने न केवल माओवादियों की साज़िशों को नाकाम किया, बल्कि भीषण गोलीबारी के बीच नज़्सलियों के सुरक्षित ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। जवानों के इस अटूट हौसले का ही परिणाम है कि भारी चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद नज़्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पिछले 24 घंटे से जारी मुठभेड़ में एक नज़्सली मारा गया, जबकि एक सी-60 कमांडो घायल हो गया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को प्रतिबंधित भारतीय कज़्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की कंपनी नंबर 10 के उग्रवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद भामराग के एसडीपीओ के नेतृत्व में 14 सी-60 यूनिटों के साथगढ़चिरौली-नारायणपुर सीमा पर फोडेवाड़ा गांव के पास यह अभियान शुरू किया गया।परिणामस्वरूप दो नज़्सली शिविरों का भंडाफोड़ हुआ। इस दौरान नज़्सलियों का सामान बरामद हुआ, हालांकि दुर्गम इलाके और घने जंगल के कारण नज़्सलियों का पता नहीं लगाया जा सका। बृहस्पतिवार की सुबह मौजूदा घेराबंदी के तहत अतिरिक्त चार सी-60 यूनिट और सीआरपीएफ की ज़्यूएटी की एक यूनिट को तैनात किया गया।'

' अधिकारी ने कहा कि आज सुबह से मुठभेड़ जारी है और अब तक एक नज़्सली का शव बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि एक एके-47 राइफल और एक सेल्फ-लोडिंग राइफल भी बरामद की गई है।

15 जिलों में 49 लाख से अधिक आबादी प्रभावित, कई नदियां उफान पर

पटना १४/०९ (संवाददाता): बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में में पिछले चार-पांच दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और 15 जिलों में करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं, कई नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बज़्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया जिलों के 88 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों के 49.36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य और पड़ोसी नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की कई नदियों और जलधाराओं का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सितंबर में अब तक 112.7 मिमी बारिश

दर्ज की गई है, जो सामान्य से लगभग छह प्रतिशत अधिक है। बुलेटिन के अनुसार, बलतारा और कुरसेला में कोसी नदी, खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी, दीघा, गांधी घाट, हथीदह, भागलपुर, कहलगांव और मुंगेर में गंगा नदी, श्रीपालपुर में पुनपुन नदी, बेनीबाद में बागमती नदी तथा दरौली में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

डीएमडी ने बताया कि बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय और अररिया शामिल हैं। सोमवार शाम छह बजे भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा 36.19 मीटर के जलस्तर पर बह रही थी, जो खतरे के निशान से 1.69 मीटर ऊपर था। अधिकारियों के मुताबिक कोसी नदी बलतारा और कुर्सेला में, बूढ़ी गंडक खगड़िया में, गंगा दीघा, गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर, कहलगांव और मुंगेर में, पुनपुन श्रीपालपुर में, बागमती बेनीबाद में और घाघरा दरौली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा 1,260 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही हैं तथा 13 राहत शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में लगभग 11,060 लोगों के लिए आवास, भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, सोमवार शाम चार बजे वाल्मीकिनगर स्थित गंडक नदी के बराज से 1,09,000 ज़्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि जलप्रवाह बढ़ने की परिपाटी बनी हुई है।

संभावित बाढ़ और राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 27 तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 10 टीम तैनात की गई हैं। वहीं, वीरपुर स्थित कोसी बराज से पानी का बहाव 1,63,315 ज़्यूसेक दर्ज किया गया। इसकी तुलना में इस वर्ष 20 जुलाई को यह अधिकतम 2,55,425 ज़्यूसेक था। इस बीच, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को केंद्र सरकार पर बाढ़ राहत के मामले में बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एज़्स' पर लिखा कि गुजरात में मामूली बाढ़ आने पर भी उदार सहायता दी जाती है, जबकि बिहार में 50 से अधिक लोगों की मौत, पशुधन की क्षति, हजारों करोड़ रुपये का नुकसान और लगभग 45 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद न तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसी राहत पैकेज की घोषणा की है।

विविध समाचार

डिप्रेशन से छुटकारा दिला सकता है चीकू

आलू की तरह दिखने वाला फल चीकू सपोटा के नाम से भी जाना जाता है। चीकू में विटामिन-बी, विटामिन ई, पोटैशियम,फाइबर और मिनरल आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। चीकू खाने से त्वचा, दिमाग और पाचन अच्छा रहता है। चीकू खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। चीकू का हर भाग स्वास्थ्य लाभों से भरा है इसके पत्ते, जड़ और छाल को औषधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं चीकू खाने से व्यक्ति को मिलते हैं कौन से गजब के फायदे।

हड्डियां बनाए रखे मजबूत

चीकू में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की हड्डियो को मजबूत बनाने का काम करता है। चीकू का रोजाना सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। चीकू खाने से बुढ़ापे की वजह से होने वाली कमजोर हड्डियों को ठीक करने में भी मदद मिलती है।

एनर्जी

चीकू को एनर्जी का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। जिन लोगों को एनर्जी की कमी महसूस होती है उनके लिए चीकू का सेवन फायदेमंद हो सकता है।

वेट लॉस

चीकू शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को लंबे समय तक भूख का अहसास नहीं होता और वेट लॉस में मिलती है। चीकू को दिन में किसी भी समय खाया जा सकता है। ये शरीर को तुरंत एनर्जी देने के साथ शरीर को मजबूत भी बनाता है।

डिप्रेशन में राहत

चीकू दिमाग को सेहतमंद बनाए रखने के साथ नींद न आने की समस्या को भी दूर करता है। चीकू का सेवन करने से गहरी और अच्छी नींद आती है। चीकू में मौजूद तत्व दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं चीकू का सेवन डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है।

इन टिप्स से रखें मेंटल हेल्थ का ख्याल

आजकल तनाव न चाहते हुए भी हम सभी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। स्ट्रेस का बुरा असर, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर होता है। अक्सर फिजिकल हेल्थ खराब होने पर जब इसके लक्षण नजर आते है, तो हम आसानी से इन्हें समझ लेते हैं और इसे ठीक करने की कोशिश में भी लग जाते हैं। लेकिन, मेंटल हेल्थ खराब होने पर इसके लक्षणों को हम या तो समझ नहीं पाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर महिलाएं अपनी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। तनाव और चिंता की वजह से अगर आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी कहीं खो गई है, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है।

मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

- एक्सपर्ट का कहना है कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, डाइट बहुत जरूरी है। डाइट में पोषक तत्वों की कमी भी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकती है।
- अगर आप अधिक तनाव में है और इसकी वजह से आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है या आप हर वक्त परेशान रहती है, तो किसी से इस बारे में खुलकर बात जरूर करें।
- ओवरथिंकिंग की वजह से भी मेंटल हेल्थ खराब होती है। इसलिए, किसी भी चीज या डर को लेकर, बहुत अधिक न सोचें वरना इसका असर आपकी सेहत पर हो सकता है।
- किसी बात को बार-बार सोचने से, स्ट्रेस और एंग्जायटी बढ़ने लगती है। इसकी वजह से सिरदर्द, शरीर में दर्द और घबराहट हो सकती है। इसलिए, ज्यादा न सोचें और मन को शांत रखने की कोशिश करें।
- एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्राणायाम भी मेंटल हेल्थ सुधारने में मदद कर सकता है। इसलिए, इसे रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं।
- जब आपको स्ट्रेस या एंग्जायटी महसूस हो, तो गहरी सांस लें और कुछ देर के लिए सारी चीजों पर से ध्यान हटाने की कोशिश करें।
- दिन में कुछ समय उन चीजों को जरूर दें, जो आपको खुशी देती हो।

पैरों के तलवे में होती है जलन इन टिप्स से मिलेगा आराम

क्या आपको भी पैरों के तलवे में जलन होती है, जलन के मारे काम करना भी मुश्किल हो जाता है तो हम आपको कुछ आजमाए हुए टिप्स बता रहे हैं जिससे आपको काफी आराम मिल सकता है। अक्सर लोगों को पैरों के तलवे में जलन की शिकायत होती है। यह एक असहज और परेशान करने वाली समस्या होती है, कई बार जलन के कारण नींद भी नहीं आती है और काम भी प्रभावित होता है। अगर आप भी इस स्थिति का सामना करते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आपको तलवे में जलन से राहत मिल सकती है।

पैरों के तलवे में जलन क्यों होती है?

- पैरों की अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसा हो सकता है। अगर आप लंबे वक्त तक जूते पहने रह सकते हैं तो इसके कारण तलवे में जलन हो सकती है।
- खराब रक्त प्रवाह के कारण भी पैरों के तलवे में जलन हो सकती है।
- शरीर में आयरन और विटामिन B12 की कमी के कारण भी यह समस्या हो सकती है।

पैरों के तलवे की जलन दूर करने के उपाय

- तलवे में अगर बहुत ज्यादा जलन होती है तो आप ठंडा पानी में 20 मिनट तक पैरों को डुबा कर रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं, इससे काफी आराम महसूस होगा।
- इसके अलावा आप तलवे में हो रही जलन को दूर करने के लिए तलवों की मालिश कर सकते है, मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जलन में आराम मिलता है।
- अपने आहार में आयरन विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व शामिल करें, इससे शरीर में खून बढ़ता है और रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलती है।
- तलवे के जलन को कम करने के लिए आप मेहंदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रात के समय पैरों में मेहंदी लगा लें और सुबह उठकर धो लें इससे तलवे में ठंडक मिलती है।
- इसके अलावा आप पैरों में एलोवेरा और चंदन का लेप लगा सकते हैं। इन दोनों ही चीजों की तासीर ठंडी होती है। इसका पेस्ट बना ले और तलवे पर भी 20 मिनट तक लगा कर रखें, फिर साफ पानी से धो लें।
- अगर इन उपायों को आजमाने के बाद भी आपको राहत नहीं मिलती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।

देखने की क्षमता प्रभावित करता है प्रेसबायोबिया विकार

प्रेसबायोबिया आंखों से जुड़ी एक बीमारी जिसमें आंखों की करीब वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है।

प्रेसबायोपिया आंखो से संबंधित एक विकार है। इस शब्द को ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बूढ़ी आंख, यह एक ऐसी स्थिति होती है जब आपकी धीरे-धीरे चीजों को करीब से स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता खो देती है। इस स्थिति में नजदीकी वस्तुओं पर तेजी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। आमतौर पर यह 40 से 45 साल की उम्र में शुरू होती है और समय के साथ बिगड़ती जाती है। यह बाकी उम्र से संबंधित दृष्टि समस्याओं जैसे अंधापन, हाइपरोपिया मायोपिया से अलग है। यह एक प्राकृतिक परिवर्तन है जो लगभग सभी लोगों को प्रभावित करता है। इसको लेकर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बाती है।

प्रेसबायोपिया के लक्षण

- छोटी लेखन सामग्री पढ़ने में कठिनाई होती है, खासकर अगर रोशनी बहुत कम है।
- जब आपको यह बीमारी होती है तो आप अपने स्मार्टफोन या किसी भी किताब, मेनू , लेबल को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी आंखों से दूर रखते हैं।
- कोई नजदीकी काम करते हैं या कुछ नजदीक रखकर पढ़ते हैं तो इसे सिर में दर्द और आंखों में तनाव होना।

प्रेसबायोपिया के कारण

- आंखों की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया प्रेसबायोपिया की ओर ले जाती है।
- समय के साथ आंखों का आंतरिक लेंस लचीला नहीं रहता है, जिससे नजदीकी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है।
- उम्र के साथ लेंस को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां कमजोर हो जाती है।
- यह अनुवांशिक भी हो सकती है। अगर आपके घर में माता-पिता या दादा- दादी कोप्रेसबायोपिया था तो आपको भी यह स्थिति होने की संभावना ज्यादा रहती है।
- डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी सहित कई स्वास्थ्य स्थितियों में भीप्रेसबायोपिया हो सकता है।
- आंखों की चोट के कारण भी लेंस को नियंत्रित करने वाले मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है,इससे भी प्रेसबायोपिया हो सकता है।

डाइट से एडेड शुगर हटाना फायदेमंद!

चीनी...यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मुंह में मिठास घुलने लगती है। चीनी जिस तरह से हर मिठाई, हलवे और खीर का स्वाद बढ़ाती है, उसी तरह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती है। वजन बढ़ने से लेकर डायबिटीज तक, चीनी शरीर के लिए कई तरह से नुकसानदायक मानी जाती है। ऐसे में कई लोगों ने चीनी को अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा दिया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो चीनी को अपनी थाली से बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं और भरपूर मीठा खा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन में कितना चीनी यानी शुगर का सेवन करना आपके लिए सेफ है।

अति किसी भी चीज की बुरी होती है, यह बात चीनी के सेवन के मामले में भी लागू होती है। डॉक्टर्स से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट भी इस बात को मानते है कि व्हाइट शुगर सेहत के लिए कई तरह से हानिकारक होती है। अब इस बात पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी मुहर लगा दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशियन ने कुछ समय पहले भारतीयों की डाइट को लेकर 17 गाइडलाइन्स की एक ज्वाइंट रिपोर्ट जारी की थी। जिसमें से एक गाइडलाइन में भारतीयों को एक दिन में कितनी शुगर लेनी चाहिए, इसका जिक्र किया गया है।

एक दिन में कितनी चीनी का सेवन करना चाहिए?

अगर एक सामान्य एडल्ट प्रति दिन 2000 कैलोरी लेता है और इसका 5 परसेंट यानी 25 ग्राम शुगर इन्टेक करता है तो वह हाई शुगर कहलाता है। अगर इसे सामान्य भाषा में समझें 20-25 ग्राम शुगर का एक दिन में सेवन किया जा सकता है।

संभव रहे तो चीनी को अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। क्योंकि इसमें कैलोरी के अलावा किसी भी तरह के न्यूट्रिशियन शामिल नहीं होते हैं। कैलोरी शरीर के लिए तभी फायदेमंद होती है जब विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर के साथ ली जाए।

रिपोर्ट के मुताबिक, एडेड शुगर को अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा देना फायदेमंद होता है। एडेड शुगर में चीनी, गुड़, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, शुगर सिरप आदि चीजें आती हैं। किसी भी चीज में शुगर को मिलाकर खाना सेहत के लिए किसी भी तरह से बेहतर नहीं होता है क्योंकि इससे शरीर में सिर्फ कैलोरी बढ़ती है। चीनी के बहुत सारे नुकसान होते है।

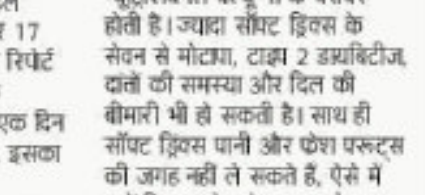

क्या नेचुरल शुगर है सेफ?

रिपोर्ट में फलों और दूध में पाई जाने वाली शुगर को नेचुरल बताया है। फलों और खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहने वाली शुगर को एक्सपर्ट भी सेफ मानते हैं, लेकिन सभी फलों और खाने की चीजों में मौजूद शुगर आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। मेडिकल बॉडी ने अपनी रिपोर्ट में गन्ने के जूस को सेहत के लिए हानिकारक माना है। गन्ने के जूस में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह आपको बीमार कर सकती है। 100 ग्राम के गन्ने के जूस में 15 ग्राम शुगर होती है, ऐसे में इसका अधिक सेवन आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर में अत्यधिक शुगर से कई बीमारियों को न्योता मिल सकता है।

रिपोर्ट में सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेवन पर भी ऐतराज जताया गया है, मेडिकल बॉडी का मानना है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिर्फ हाई शुगर कंटेंट होता और न्यूट्रिशियनल वैल्यू ना के बराबर होती है। ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेवन से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दांतों की समस्या और दिल की बीमारी भी हो सकती है। साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक्स पानी और फ्रेश फ्रूट्स की जगह नहीं ले सकते हैं, ऐसे में उन्हें जितना हो सके इनका सेवन करने से बचना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह छाछ, नींबू पानी, बिना चीनी वाले फ्रूट जूस और नारियल पानी के सेवन की सलाह दी गई है। जूस से ज्यादा फलों के सेवन पर भी जोर दिया है। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि फ्रूट फाइबर और न्यूट्रियंट वैल्यू की वजह से ज्यादा सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

गाइडलाइन्स में भारतीयों की हेल्दी डाइट पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में हरी सब्जियों के अत्यधिक सेवन की बात की गई है और डाइट से प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक को हटाने की सलाह दी गई है। साथ ही चाय और कॉफी के सेवन को भी कम करने की बात की गई है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक साबित साबित हो सकता है।

कलिंग समाचार

संपादकीय

कॉम्प्रोमाइज़्ड कौन है

पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, कांग्रेस का ये नया सूत्रवाक्य इस समय मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। राहुल गांधी ने ये बात संसद में कही, इसके बाद इसी वाक्य वाले टी शर्ट्स के साथ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने भोपाल में किसान महापंचायत में अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते का सच बताते हुए भी यही वाक्य कहा और किसानों को बताया कि कैसे उनके भविष्य को खतरे में डालकर नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के साथ भारत के लिए घाटे का सौदा किया है। काम्प्रोमाइज़्ड शब्द का असर इतना गहरा हुआ कि अब भाजपा ने भी इसी का इस्तेमाल गांधी परिवार पर हमला करने के लिए किया। बुधवार को पीयूष गोयल ने एक पोस्ट में पं.नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी इन सबके नाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़्ड लिखकर आरोप लगाया कि चारों के सत्ता में रहने के दौरान भारत में क्या-क्या गलत हुआ। नेहरूजी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं हैं, वहीं सोनिया गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं रहीं, यूपीए के दोनों कार्यकाल में डॉ.मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे। हालांकि भाजपा ने उनके जीवित रहते कई बार उनका अपमान किया और मृत्यु के बाद अंतिम विदाई में भी अनादर ही किया। लेकिन गनीमत है कि कॉ प्रोमाइज़्ड शब्द का इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया। वैसे भी भाजपा के निशाने पर गांधी परिवार और अभी खासतौर पर राहुल गांधी ही रहते हैं। तो भाजपा ने यही कहा कि राहुल गांधी का पूरा परिवार ही कॉ प्रोमाइज़्ड है। भाजपा को मुगालता है कि उसके ऐसे हमलों से अब वो सवाल उठने बंद हो जाएंगे, जिन पर नरेन्द्र मोदी बुरी तरह घिरे हुए हैं। लेकिन उसके लिए ज्यादा झटके वाली बात यह रही कि जिस समय गांधी परिवार पर वह हमला बोल रही थी, उसी समय कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने करीब एक घंटे की प्रेस कांफ्रेंस बुधवार को की। इस में उन्होंने एपस्टीन फाइल्स पर आधारित कुछ ऐसे खुलासे किए, जिनके बाद हर देशवासी को डरना चाहिए कि आखिर देश की सत्ता किनके हाथों में है। भाजपा ने अपनी राजनीति को राम मंदिर के मुद्दे पर आगे बढ़ाया, बाबरी मस्जिद तोड़ी, वहीं पर राम मंदिर बनवा लिया और उसके बाद देश-विदेश के मंदिरों में नरेन्द्र मोदी को जी भर के पूजा पाठ करते हुए लोगों ने देखा है। हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के साथ-साथ मुस्लिम अल्पसं यकों पर अत्याचारों को भी खूब बढ़ावा मिला और बड़े पैमाने पर नफरत फैलाने का काम भाजपा ने सफलतापूर्वक किया। ये कामयाबी उसे धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर मिली। लेकिन एपस्टीन फाइल्स के खुलासों ने फिर जाहिर कर दिया है कि धर्म तो भाजपा की राजनीति का केवल आवरण है, असल में विदेशी भ्रष्ट ताकतों के हाथों में देश की कमान देने का खेल भाजपा की राजनीति की असलियत है। इससे पहले अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार भी देश में रही, तब भी घरेलू स्तर पर धार्मिक संकीर्णता कई मौकों पर जाहिर हुई, लेकिन विदेश नीति और रक्षा नीति परंपरागत तरीके से ही चलती रही। उनमें कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ, जिससे लगे कि हम अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन 2014 से हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। पवन खेड़ा ने बताया कि एपस्टीन फाइल्स में पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी, उद्योगपति अनिल अंबानी, खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले दीपक चोपड़ा, इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक, मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और खुद जेफ्री एपस्टीन इन सबके बीच भारत की विदेश नीति और अमेरिका या इजरायल से किए जा रहे रक्षा सौदों को लेकर जो बातचीत 2014 से 2017 के बीच लगातार हुई हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय या अमेरिका या अन्य देशों में हमारे दूतावास केवल दिखावे के हैं। इनसे जुड़े फैसले लेने की असली ताकत जेफ्री एपस्टीन और उसके गिरोह के पास ही है। एपस्टीन तो अब मर चुका है, लेकिन उससे हरदीप पुरी के संबंध स्थापित होने के बावजूद प्रधानमंत्री उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर रहे, उस पर पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी अपने ही मंत्री के दबाव में हैं।

मोदी जी, कृपया कभी तो प्रधानमंत्री की तरह बोलिए

अनिल जैन

राज्यसभा में उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो भाषण दिया, उसमें भी न तो न्यूनतम संसदीय मर्यादा और शालीनता का समावेश था और न ही पद की गरिमा व लोकतांत्रिक परंपरा की कोई झलक थी। स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का समापन करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित मुद्दों पर अपनी सरकार का नज़रिया पेश करते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के दौरान का उनका एक भी ऐसा भाषण याद नहीं आता जो उन्होंने इस विशाल देश के प्रधानमंत्री की तरह दिया हो।

अधूरा सच, सफ़ेद झूठ, आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर गलत बयानी, तथ्यों की मनमाने ढंग से तोड़-मरोड़, परनिंदा, पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति हिकारत का भाव, नए-नए शिगूफ़े, स्तरहीन मुहावरे, राजनीतिक विरोधियों पर छिछले कटाक्ष, नफ़रत भरी सांप्रदायिक तल्खी, धार्मिक व सांप्रदायिक प्रतीकों का इस्तेमाल और भरपूर आत्म प्रशंसा! यही सब प्रमुख तत्व होते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में। मौका चाहे देश में हो या विदेश में, संसद में हो या किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर, चुनावी रैली हो या कोई और अवसर- हर जगह उनके भाषण में अहंकारयुक्त हाव-भाव के साथ यही सारे तत्व हावी रहते हैं। पिछले सप्ताह गुरूवार (5 फरवरी) को राज्यसभा में दिया गया भाषण भी इसका अपवाद नहीं रहा।

वैसे तो मोदी को संसद के दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देना था, लेकिन लोकसभा में 4 फरवरी को उन्होंने भाषण नहीं दिया। ऐसा उन्होंने %लोकसभा स्पीकर के कहने पर% किया। स्पीकर ओम बिड़ला ने बेहद हास्यास्पद और शर्मनाक %आशंका% जताई थी कि प्रधानमंत्री अगर सदन में भाषण देने आएंगे तो कांग्रेस की कुछ महिला सांसद उन पर हमला कर सकती हैं। स्पीकर की इस आशंका से वह प्रधानमंत्री डरकर सदन में नहीं आए, जिसने तीन साल पहले 10 फरवरी, 2023 को संसद में ही अपनी पीठ थपथपाते हुए बेहद फूहड़ अंदाज़ में कहा था, %देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है।

बहरहाल राज्यसभा में उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो भाषण दिया, उसमें भी न तो न्यूनतम संसदीय मर्यादा और शालीनता का समावेश था और न ही पद की गरिमा व लोकतांत्रिक परंपरा की कोई झलक थी। स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित मुद्दों पर अपनी सरकार का नज़रिया पेश करते हैं। इसी क्रम में वे बहस के दौरान विपक्ष के आरोपों और आलोचनाओं का भी जवाब देते हैं। मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं किया। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने इस गंभीर मौके पर भी एक मोहल्ला स्तर के नेता की तरह चुनावी भाषण दिया। कुछ साल पहले फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि %देश को असली आजादी तो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मिली है।% कंगना की इस बात पर खुश होकर मोदी ने उन्हें सांसद बनवा दिया और गुरूवार को राज्यसभा में कंगना द्वारा कही बात की तज़र्पर ही यह जताने की कोशिश की कि देश ने जो कुछ तरक्की की है, वह उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद की ही है।

उन्होंने कहा कि उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें किसी के पास देश को लेकर न तो कोई सोच थी, न कोई दृष्टि और न ही इच्छाशक्ति। उन्होंने देश को बर्बाद करके रखा हुआ था। उन्होंने कहा, मैं देशवासियों का आभारी हूं कि उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। हमारी काफी शक्ति उनकी (पूर्व प्रधानमंत्रियों की) गलतियों को ठीक करने में लग रही है।

उनके समय जो देश की छवि बनी थी, उसे धोने में मेरी ताकत लग रही है। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की आलोचना व निंदा करने का तो मोदी पर मानो जुनून सवार रहता है और इस सिलसिले में जो मुंह में आता है वह बोल जाते हैं। ऐसा करने में वे इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उनकी अशोभनीय गलतबयानी से देश-दुनिया में उनकी खिल्ली उड़ेगी और लोग उनकी पढ़ाई-लिखाई व उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाएंगे। राज्यसभा में दिए अपने भाषण में भी मोदी ऐसा करना नहीं भूले। इस सिलसिले में उन्होंने इंदिरा गांधी के ईरान में दिए गए एक भाषण के हवाले से कहा कि, जवाहरलाल नेहरू के समय देश की जनसं या 35 करोड़ थी और नेहरू कहते थे कि मेरे सामने 35 करोड़ समस्याएं हैं।

इसी तरह इंदिरा गांधी के समय देश की जनसं या 57 करोड़ थी और इंदिरा जी ने कहा था कि, मेरे सामने 57 करोड़ समस्याएं हैं। मोदी का यह बताना या तो उनकी क्षुद्रता का परिचायक है या फिर उनकी नासमझी का। यह उनके भाषण के नोट्स बनाने वाले नौकरशाहों की शरारत भी हो सकती है कि उन्होंने मोदी को गलत नोट्स बनाकर थमा दिए हों जिन्हें मोदी ने संसद में पढ़ दिए।

दरअसल नेहरू से जब किसी विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि %आपके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो नेहरू ने कहा था कि देश के 35 करोड़ लोगों की समस्याएं मेरी समस्या है; और इसी तरह इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश के 57 करोड़ लोगों की समस्याओं को मैं अपनी समस्या मानती हूं। प्रधानमंत्री अपने भाषण का स्तर गिराने में यहीं नहीं ठहरे। इससे भी नीचे उतरते हुए उन्होंने कहा कि चोरी करना नेहरू-गांधी परिवार का पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती महात्मा गांधी का सरनेम तक चुरा लिया।

वैसे अव्वल तो कोई क्या सरनेम लगाता है, यह बहस का विषय नहीं हो सकता और संसद में तो कतई नहीं, फिर भी अगर मोदी को इसका शौक है तो उन्हें इस बारे में बोलने से पहले यह जान लेना चाहिए कि गांधी सरनेम किसी जाति या संप्रदाय विशेष में नहीं होता है बल्कि यह इत्र-फुलेल से जुड़े व्यवसाय से ताल्लुक रखता है। यह सरनेम सिर्फ वैश्य वर्ग में ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, पारसी आदि समुदायों में भी होता है। मोदी ने यह सिलसिला सिर्फ चुनावी सभाओं तक ही सीमित नहीं रखा है।

संसद में, संसद के बाहर विभिन्न मंचों पर और यहां तक कि विदेशों में भी वे विपक्षी नेताओं पर निजी हमले और अपमानजनक बातें करने से नहीं चूकते हैं। फिर, विपक्ष शासित राज्यों के प्रति उनकी सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार ने भी केंद्र और राज्यों के बीच खटास पैदा कर दी है। दरअसल विरोधी दलों और उनके नेताओं के प्रति मोदी की अपमानजनक बातें शुरू में जरूर अटपटी लगती थीं।

चूंकि भाजपा और मोदी ने काफी बड़ी जीत हासिल की थी, इसलिए विपक्षी नेताओं ने उनकी ऐसी बातों को यह सोचकर बर्दाश्त किया कि जीत की खुमारी उतर जाने पर प्रधानमंत्री राजनीतिक विमर्श में सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार और भाषायी शालीनता का पालन करने लगेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ और लगने लगा कि यही मोदी की स्वाभाविक राजनीतिक शैली है और वे बदलने वाले नहीं हैं, तब विपक्षी नेताओं के सब्र का बांध टूटा और उसमें सारी राजनीतिक शालीनता और मर्यादा बहती चली गई।

ज़्यादा जानें बॉलीवुड मूवी टिकट कविता संग्रह साक्षात्कार तकनीक गाइड देश में शायद ही कोई ऐसा विपक्षी मु यमंत्री या नेता होगा जिसके लिए पीएम ने सार्वजनिक रूप से अपमानजनक बातें या गाली-गलौज नहीं की होगी। मोदी उन्हें भ्रष्ट, परिवारवादी, लुटेरा, नक्सली, आतंकवादियों का समर्थक और देशद्रोही तक करार देने में कोई संकोच नहीं करते। इस सिलसिले में वे विपक्ष की महिला नेताओं को भी नहीं ब. शते। वे उनके लिए बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। विपक्षी नेताओं के प्रति मोदी के अपमानजनक बर्ताव का ही नतीजा है कि आज केन्द्र-राज्य संबंध किसी भी समय के मुकाबले सबसे बदतर स्थिति में हैं। हाल के वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब मोदी किसी विपक्ष शासित राज्य के दौरे पर गए तब वहां के मु यमंत्री उनकी आगवानी करने नहीं पहुंचे।

प्रधानमंत्री ने तमाम विपक्षी दलों को अपने, अपनी पार्टी और देश के दुश्मन के तौर पर प्रचारित करते हुए उन्हें खत्म करने का खुला ऐलान किया है।

वे हर जगह डबल इंजन की सरकार का ऐसा प्रचार करते हैं, जैसे विपक्ष की सारी सरकारें जनविरोधी, देश-विरोधी और विकास-विरोधी हैं। मोदी की इस राजनीति ने विपक्षी पार्टियों को सोचने पर मजबूर किया है। इसलिए आज अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर आंच आ रही है और उनकी बेअदबी हो रही है तो इसके लिए प्रधानमंत्री का अंदाज़-ए-हुकूमत और अंदाज-ए-सियासत ही जि मेदार है। कितना अच्छा होता कि मोदी भाषा और संवाद के मामले में भी उतने ही नफासत पसंद या सुरुचिपूर्ण होते, जितने वे पहनने-ओढ़ने और सजने-संवरने के मामले में हैं। एक देश अपने प्रधानमंत्री से इतनी सामान्य और जायज अपेक्षा तो रख ही सकता है। उनका बाकी अंदाज-ए-हुकूमत चाहे जैसा भी हो।

भारत पर नजर रखो, क्या दिन ला दिए मोदी जी!

शकील अख्तर

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यह तो बता रहे हैं कि कौन कौन से उत्पाद भारत में नहीं आएंगे। मगर यह नहीं बता रहे कि कौन कौन से आएंगे। सारा खेल इसी में छुपा है। अमेरिका जो चाहेगा वह आएगा। जीएम (जेनेटिक मोटिफाइड) फसलों के लिए वह भारत को प्रयोगशाला बनाएगा। यही कहा जा रहा है कि मीडिल क्लास चेत जाए। यह जीएम फसलें इस पीढ़ी को नहीं अगली कई पीढ़ियों को क्या नुकसान पहुंचाएंगी यह सोचना भी बहुत डरावना है। डीएनए बदल जाएगा।

किसी से लड़ना, अवाइड करना या और कुछ भी तिरस्कार वगैरह इन सबसे बुरी बात समझी जाती है नजर रखना। नजर किस पर रखी जाती है? वह तो सब ठीक है अपराधी वगैरह। लेकिन उससे भी बुरी बात है नजर अपने आश्रित पर रखी जाती है। शब्द बहुत गंदा है मगर सच वही है कि गुलाम पर। कि वह गुलामी से बाहर जाने की तो नहीं सोच रहा। नजर रखो इस पर। ज़्यादा जानें भाषा सीखने का कोर्स ऑनलाइन समाचार पोर्टल साक्षात्कार तो मोदी जी आज भारत को इस स्थिति पर ले आए कि अमेरिका के अधिकारी हम पर निगाह रखेंगे। अब क्या कहें? हद तो यह हो गई कि इस शर्मनाक स्थिति में लाने को मोदी अपनी शान समझ रहे हैं! संसद परिसर में एनडीए के सांसदों से अपना स्वागत करवा रहे हैं। हार पहन रहे हैं। जीत का!

हम किस से तेल खरीदेंगे किस से नहीं यह अमेरिका तय करेगा। और हम उसके अनुसार करेंगे। मगर फिर भी वह हम पर निगाह रखेगा। इससे ज्यादा शर्म की, अपमान की बात और क्या हो सकती है। लेकिन क्या यह भारत का अपमान है? ऊपर से देखने में हैं। मगर वास्तव में यह मोदी का पराभव है। सारी नकली कलई खुल गई। 56 इंच की छाती, लाल आंखों और एक अकेला सब पर भारी की असलियत सब के सामने आ गई। अमेरिका के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। राहुल गांधी के शब्दों में नरेन्द्र ...सरेन्डर!, द्यह्यश ऋद्धड्डस्र - उलटा पड़ सकता है किताब को लेकर मुकदमे का दांव बाहर इस तरह सरेन्डर किया और यहां राहुल का सामना होने से डर कर लोकसभा में नहीं आए। राहुल ने सुबह कहा था मोदी जी में लोकसभा में आने की हि मत नहीं है। उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना था। मगर वे वास्तव में नहीं आए और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष से कहलवाया यह गया कि मोदी को सदन में खतरा था। विपक्ष की महिला सांसदों से। इसलिए नहीं आए।

प्रधानमंत्री को सदन के अंदर खतरा! वह भी महिला सांसदों से! बहुत बड़ा मजाक हो गया यह। और यहीं से मोदी जी की उलटी गिनती की शुरुआत हो जाती है। विदेशों से भारत की निगरानी का फरमान आता है और उन्हें जवाब देना तो दूर वे देश में अपनी लोकसभा में जिसके वे नेता हैं वहां इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें वहां खतरा दिखता है। द्यह्यश ऋद्धड्डस्र - एक हाथ से ताली नहीं बजती अमेरिका से डील मोदी की है। कमजोर और लाचार भारत दिख रहा है। भारत न कभी था न कभी है। लेकिन जैसा कि भक्तों ने मोदी का मतलब भारत कर दिया था। वैसा ही अब मोदी के कमजोर होने से अमेरिका भारत को कमजोर समझ रहा है। उस पर नजर रखने की बात कर रहा है। इसका जवाब विपक्ष तो कड़े शब्दों में दे ही रहा है।

कांग्रेस ने साफ कह दिया कि आपकी जो भी सीक्रेट अमेरिका के पास हों हमें कोई मतलब नहीं है। आप इस वजह से सरेंडर कर दीजिए मगर भारत नहीं झुकेगा। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चैयरमेन पवन खेड़ा ने यह कहते हुए एपस्टीन फाइल का भी ज़िक्र किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कर चुके हैं। एपस्टीन फाइल में नाम आया है। संदेश यही जा रहा है कि एपस्टीन फाइल की वजह से ट्रंप मनमानी कर रहा है।

पहले उसने सीज फायर करवाया। और फिर यह डील। जो पूरी तरह इकतरफा है। भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ। भारत का जो सामान पहले अमेरिका 3 परसेन्ट टैरिफ देकर जाता था। अब 18 परसेन्ट देकर जाएगा। सामान्य शब्दों में पहले भारत के बने सामान पर अमेरिका केवल तीन प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) लेता था। फिर उसने हमें धमकाते हुए पहले 50 प्रतिशत किया। सौ प्रतिशत की धमकी दी। फिर 25 प्रतिशत पर लाया। और अब जो नई डील हो गई है उस में 18 प्रतिशत लेगा। मतलब तीन से 18 प्रतिशत बढ़ाया गया है और हमारे प्रधानमंत्री इस अपनी जीत बताते हुए विजय माला पहन रहे हैं।

ज़्यादा जानें क्षेत्रीय व्यंजन रेसिपी चुनावी कवरेज राजनीतिक विश्लेषण और देखिए! डील में इससे भी ज्यादा जो खतरनाक पहलू है जिसे सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है वह है अमेरिका के लिए अपना पूरा बाजार खोल देना। अमेरिका कह रहा है कि इस डील से उसका किसान मालामाल हो जाएगा। और हमारे किसान का दिवाला निकल जाएगा। अमेरिका से जो कृषि और डेयरी उत्पाद आएंगे वह टैरिफ फ्री होंगे। मतलब उस पर भारत एक पैसा भी शुल्क (टैरिफ) नहीं लगाएगा। अमेरिका को जो भी अतिरिक्त उत्पादन है वह सब यहां डंप किया जाएगा। भारत का किसान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि यह तीन काले कानूनों से बड़ी तबाही होने जा रही है। उसके साफ शब्द हैं कि उन्हें सरकार की सफाइयों पर भरोसा नहीं है। डील में जितना बताया जा रहा है उससे ज्यादा छुपाया जा रहा है। अमेरिका का साफ कहना है वह इसके जरिए 500 अरब डालर का माल भारत में बेचेगा। 500 अरब डालर मतलब 45 लाख करोड़ रुपए! यह भी समझना मुश्किल है इतना रुपया कितना होता है? तो थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि अभी जितना माल विदेशों से भारत आता है उसका ढाई गुने से ज्यादा केवल अमेरिका से हमें आयात करना होगा। और माल आता हो तो किसका पैसा जाता है। आम भारतीय का ही।

उससे यही माल खरीदवाया जाएगा। किसकी कीमत पर? भारतीय किसान और पशुपालक की कीमत पर। प्रचार और कीमतों में का पीटिशन करवा कर वे भारतीय किसान को मुकाबले से बाहर कर देंगे। खतरे बहुत बड़े हैं। जनता को ही समझना होंगे। और अगर नहीं समझती तो वह आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी की कहानी लिखने में खुद भी शामिल मानी जाएगी। कांग्रेस ने मध्यम वर्ग को सचेत किया है।

माहौल वही बनाता है। मोदी मोदी का जाप सबसे पहले उसी ने किया था। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यह तो बता रहे हैं कि कौन कौन से उत्पाद भारत में नहीं आएंगे। मगर यह नहीं बता रहे कि कौन कौन से आएंगे। सारा खेल इसी में छुपा है। अमेरिका जो चाहेगा वह आएगा। जीएम (जेनेटिक मोटिफाइड) फसलों के लिए वह भारत को प्रयोगशाला बनाएगा। यही कहा जा रहा है कि मीडिल क्लास चेत जाए। यह जीएम फसलें इस पीढ़ी को नहीं अगली कई पीढ़ियों को क्या नुकसान पहुंचाएंगी यह सोचना भी बहुत डरावना है। डीएनए बदल जाएगा। यह संयोग प्रयोग डीएनए ऐसे शब्दों का प्रधानमंत्री बहुत उपयोग करते हैं। मगर क्या इनका मतलब उन्हें मालूम है? भारत में जीएम फसलों पर रोक है। केवल कपास की खेती की अनुमति है। यह बहुत बड़ी बहस है कि खाने-पीने की चीजें जीएम होना चाहिए या नहीं और इसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रयोग भारतीय लोगों पर किया जाएगा? बहुत संक्षेप में जीएम मतलब किसी बीज, जीव या पौधे के जीन को दूसरे में आरोपित कर एक नई प्रजाति विकसित करना। जीएम फसलों की जरूरत वहां होती है जहां उत्पादन कम हो। मगर भारत में तो इन्दिरा गांधी ने हरित क्रान्ति करके देश में अतिरिक्त अनाज पैदा करवा दिया था। किसान और कृषि वैज्ञानिकों ने उनका साथ दिया था। वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल ने कहा है कि भारत ने अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पाद व्यापार में मौजूद पुरानी बाधाओं को पार करने पर सहमति जताई है। इससे साफ और क्या होगा? सरकार कितना ही छुपाने की कोशिश करे इसका मतलब साफ है जीएम फसलों के लिए दरवाजे खोलना।

विविध समाचार

पंजाब के राज्यपाल और केंद्रीय राज्य मंत्री ने 1,044 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

लुधियाना। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर सन फाउंडेशन द्वारा संचालित मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटरों (एमएसडीसी) का भव्य दीक्षांत समारोह आज वर्ल्ड स्किल कैंपस ऑफ एक्सीलेंस, गवर्नमेंट आईटीआई कैंपस, गिल रोड, लुधियाना में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान सन फाउंडेशन के पंजाब भर में संचालित कौशल केंद्रों से प्रशिक्षित 1,044 युवाओं को प्रमाण–पत्र एवं नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह में पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की मेजबानी पद्मश्री डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी, राज्यसभा सांसद एवं सन फाउंडेशन के चेयरमैन ने की। इस कार्यक्रम में पंजाब भर से 3,000 से अधिक युवाओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों, नियोक्ताओं तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया, जिससे यह राज्य में विश्व युवा कौशल दिवस के सबसे बड़े आयोजनों में से एक बन गया। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के क्षेत्र में सन फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की। उन्होंने पद्मश्री डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी के दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि फाउंडेशन की पहलें पंजाब के हजारों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बना रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने पंजाब में विश्वस्तरीय कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए पद्मश्री डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी और सन फाउंडेशन की टीम की प्रशंसा की।

उन्होंने सन फाउंडेशन को कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक आदर्श संस्था बताया तथा युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में डॉ. साहनी के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं सन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि कौशल विकास और रोजगार सृजन, पंजाब में बेरोजगारी, नशाखोरी और पलायन जैसी चुनौतियों का सबसे प्रभावी समाधान हैं। उन्होंने बताया कि सन फाउंडेशन आज अपने मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटरों के नेटवर्क के माध्यम से उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देकर प्रतिवर्ष 5,000 से अधिक युवाओं को "स्किल फॉर जॉब्स" उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि सन फाउंडेशन के केंद्रों से प्रशिक्षित हजारों युवाओं को इंडिगो एयरलाइंस, ताज होटल्स, मैरियट, रेडिसन, शाही एक्सपोर्ट्स, एवन साइकिल्स सहित विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और सेवा क्षेत्र की अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार प्राप्त हुआ है। डॉ. साहनी ने कहा कि सन फाउंडेशन उद्योगों की आवश्यकताओं और युवाओं की आकांक्षाओं के बीच की दूरी को सफलतापूर्वक कम कर रहा है। संस्था बाजार की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार कर युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर रही है। समारोह के दौरान गणमान्य अतिथियों ने वर्ल्ड स्किल कैंपस ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया। उन्होंने प्रशिक्षुओं से संवाद किया तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य सेवा और अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित कौशलों की प्रदर्शनी एवं लाइव डेमोंस्ट्रेशन का अवलोकन किया।

हरभजन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सुरक्षा बहाल करने से साफ किया इंकार

जालंधर। पंजाब से राज्यसभा सांसद और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी (आप) छोड़ने के बाद वापस ली गई पंजाब पुलिस की सुरक्षा को बहाल करने की भज्जी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि रिकॉर्ड देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पार्टी छोड़ने की वजह से अचानक उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। इस फैसले ने सुरक्षा बहाल होने की उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हरभजन सिंह ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करते हुए तर्क दिया था कि आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहने के दौरान उनके पास करीब 25 पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा था। सांसद के मुताबिक, उन्होंने 24 अप्रैल 2026 को पार्टी से इस्तीफा दिया था और ठीक अगले ही दिन यानी 25 अप्रैल को पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा अचानक हटा ली। हरभजन का आरोप था कि यह फैसला बिना किसी समीक्षा और बिना उनका पक्ष सुने लिया गया। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि उनके जालंधर स्थित आवास के बाहर भारी प्रदर्शन हुआ था और उन्हें 'गद्दार' बताने वाले पोस्टर भी लगाए गए थे, जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा बना हुआ है। इस पूरे मामले पर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा। राज्य सरकार ने बताया कि हरभजन सिंह की सुरक्षा वापस लेने का फैसला उनके आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद नहीं लिया गया था। दरअसल, यह निर्णय बहुत पहले 3 मार्च 2026 को ही सुरक्षा समीक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में हुए मूल्यांकन के आधार पर ले लिया गया था। समिति को किसी भी खुफिया एजेंसी से सांसद की जान को खतरे का कोई इनपुट नहीं मिला था। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि भज्जी की पंजाब में गतिविधियां बेहद सीमित हैं और वे ज्यादातर समय राज्य से बाहर ही रहते हैं।

हालांकि, जब भी वे पंजाब आएंगे, तो जालंधर पुलिस द्वारा उन्हें स्थानीय स्तर पर जरूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरभजन सिंह की चिंताओं पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केवल घर के बाहर प्रदर्शन होने या पोस्टरों पर 'गद्दार' लिख दिए जाने से जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई वास्तविक खतरा साबित नहीं होता है, खासकर तब जब प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा न हुई हो। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 4 मई 2026 को ही हरभजन सिंह को सीआरपीएफ के जरिए वाई–प्लस श्रेणी की कड़ी सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। केंद्र की सुरक्षा और पंजाब सरकार के स्थानीय सुरक्षा देने के पक्के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने भज्जी की याचिका का निपटारा कर दिया।

सभी मतदान केंद्रों पर एक दिवसीय एसआईआर विशेष शिविर लगाया जाएगा

चंडीगढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का घर–घर गणना चरण इस समय पूरे पंजाब में जारी है और यह 3 अगस्त तक चलेगा। इस प्रक्रिया को और अधिक सुचारु एवं प्रभावी बनाने के लिए राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 800 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक एक दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, ताकि मतदाता अपने गणना प्रपत्र भरकर वहीं जमा कर सकें। राज्य के मतदाताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आईएएस ने कहा, "यदि आपने अभी तक अपना गणना प्रपत्र नहीं भरा है, तो तुरंत अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करें अथवा इस विशेष शिविर के दौरान अपने निकटतम मतदान केंद्र पर जाकर प्रपत्र भरें और जमा करें। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम 13 अगस्त, 2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।"

भारतीय परंपरा में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और जनसांख्यिकीय संतुलन

वर्तमान राजनीतिक विमर्श में धर्मनिरपेक्षता शब्द को एक विशेष पाश्चात्य दृष्टि से देखा जाता है, जहां राज्य और चर्च (धर्मसत्ता) के पृथक्करण को ही इसका मूल आधार माना गया है, किंतु भारतीय वांग्मय में धर्म शब्द का अनुवाद रिलिजनया पंथके रूप में करना एक वैचारिक त्रुटि है। भारत की आत्मा पंथनिरपेक्ष हो सकती है, किंतु वह कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय मनीषा में धर्म का अर्थ कर्तव्य, सदाचार, न्याय और सार्वभौमिक नियम है।यदि भारत की जनसांख्यिकी में एक आमूलचूल परिवर्तन की कल्पना की जाए, जहां 100 करोड़ मुस्लिम मतावलम्बी और 30 करोड़ हिंदू धर्मावलम्बी हों, तो क्या भारत का यह सहिष्णु, समावेशी और सर्वपंथसमादर का स्वरूप अक्षुण्ण रह पाएगा? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर केवल तात्कालिक राजनीतिक सिद्धांतों में नहीं, अपितु भारत के प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक अनुभवों और सांस्कृतिक चेतना के गहन विश्लेषण में अंतर्निहित है।भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक नियति को समझने के लिए हमें वैदिक और पौराणिक सिद्धांतों का आश्रय लेना होगा। यह सूत्र केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि भारत की शासन व्यवस्था और सामाजिक ताने–बाने का मूलाधार रहा है। सत्य एक है, उसे जानने और अभिव्यक्त करने के मार्ग भिन्न हो सकते हैं। इसी भांति, मत्स्य पुराण और महाभारत के शांतिपर्व में राजधर्म की जो व्याख्या की गई है, वह किसी भी राजा को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के आधार पर प्रजा में भेद करने की अनुमति नहीं देती। सनातन भारतीय परंपरा में राज्य का चरित्र स्वाभाविक रूप से समावेशी रहा है, क्योंकि वहां वसुधैव कुटुम्बकम् (महामहोपनिषद) और सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना की जाती है। जब हम 100 करोड़ मुस्लिम और 30 करोड़ हिंदू जनसंख्या के परिदृश्य की विवेचना करते हैं, तो हमें दो सर्वथा भिन्न दार्शनिक प्रणालियों के अंतर्संबंधों को समझना होगा।सनातन बहुत्ववाद हिंदू चिंतन में मुक्ति के अनेक मार्ग (ज्ञान, कर्म, भक्ति) स्वीकार्य हैं। यहां नास्तिक को भी चार्वाक ऋषि कहकर सम्मानित किया गया है। इसलिए बहुसंख्यक हिंदू समाज में अन्य पंथों को फलने–फूलने का नैसर्गिक अधिकार मिला।लेकिन अब्राहमिक एकेश्वरवाद इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार शासन और समाज का संचालन शरीयत के सिद्धांतों के आलोक में होता है। पारंपरिक इस्लामी राजनीतिक दर्शन विश्व को दो भागों में विभाजित करता है– दार–उल–इस्लाम (इस्लामी भूमि) और दार–उल–हर्ब (संघर्ष की भूमि)।यदि भारत में मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक लगभग 75 प्रतिशत हो जाती है, तो देश का संविधान और उसका धर्मनिरपेक्ष ढांचा इस बात पर निर्भर करेगा कि तत्कालीन नेतृत्व इस्लाम के किस व्याख्यात्मक स्वरूप को स्वीकार करता है।यदि सूफी व रहस्यवादी दृष्टिकोण, कबीर, रसखान, दारा शिकोह और सूफी संतों की समन्वयात्मक परंपरा प्रभावी रहती है, तो भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता को अक्षुण्ण रख सकता है।लेकिन इसके विपरीत रूढ़िवादी व कट्टपंथ का प्रभाव वाले वहाबी, सलाफी या देवबंदी जैसी रूढ़िवादी विचारधाराओं का प्रभुत्व बढ़ता है, तो राज्य का चरित्र धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष न रहकर एक इस्लामी गणराज्य के रूप में परिवर्तित होने की संभावना प्रबल हो जाती है, जैसा कि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में देखा गया है। इतिहास इस बात का जीवंत साक्षी है कि किसी भी भूभाग का सांस्कृतिक और राजनैतिक चरित्र वहां के बहुसंख्यक समाज की धार्मिक मान्यताओं से निर्धारित होता है। वैश्विक स्तर पर ऐसे उदाहरण अत्यंत विरल हैं, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले राष्ट्र ने पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष और गैरमजहबी शासन व्यवस्था को स्वीकार किया हो।तुर्की ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया था, किंतु विगत कुछ दशकों में वह भी पुनः अपनी रूढ़िवादी इस्लामी पहचान की ओर लौट रहा है। इंडोनेशिया एक अपवाद अवश्य प्रतीत होता है, जहां जनसांख्यिकी मुस्लिम बहुल होने के बाद भी पंचशील के सिद्धांत के कारण सांस्कृतिक धरातल पर रामायण और महाभारत से जुड़ाव बना हुआ है। किंतु वहां भी हाल के वर्षों में कट्टरपंथ की सुगबुगाहट बढ़ी है।शाश्वत सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था उसकी आत्मिक चेतना से प्रस्फुटित होती है। भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की तरह राज्य और धर्म के कृत्रिम अलगाव पर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के सर्वपंथ समादर पर टिकी है।यदि जनसांख्यिकी का संतुलन उलट जाता है, तो भारत के वर्तमान लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखना एक अत्यंत दुरूह और अभूतपूर्व चुनौती होगी। 30 करोड़ अल्पसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार तभी तक सुरक्षित रह पाएंगे, जब तक भारत का भावी बहुसंख्यक समाज अपनी प्राचीन समन्वयात्मक और सूफी विरासत को जीवित रखेगा तथा मध्यकालीन आक्रामक पंथ–विस्तार की नीति का परित्याग करेगा। आधुनिक वैश्विक राजनीति में नागरिक अधिकारों और पंथनिरपेक्षता की कसौटी इस बात से आंकी जाती है कि कोई राज्य अपने अल्पसंख्यकों को कितनी स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्रों ने जहां धर्म और राज्य को पृथक कर नागरिक समानता को सर्वोपरि माना, वहीं इस्लामी राजनीतिक दर्शन में राज्य, समाज और मजहब के अंतर्संबंधों का एक भिन्न स्वरूप दिखाई देता है।वैश्विक स्तर पर मुस्लिमबहुल देशों, मलेशिया से लेकर मोरक्को तक का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति केवल आधुनिक संविधानों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है कि उस राष्ट्र ने अपनी शासन व्यवस्था में शरीयत (इस्लामी कानून) और मजहबी परंपराओं को किस सीमा तक स्थान दिया है?मुस्लिमबहुल देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को शासन प्रणालियों में विभक्त कर समझा जा सकता है–पूर्ण धर्मशास्त्रीय मॉडल, संवैधानिक रूप से इस्लामी किंतु मिश्रित मॉडल और सैद्धांतिक पंथनिरपेक्ष मॉडल।पूर्ण धर्मशास्त्रीय मॉडल का उदाहरण, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान (तालिबान शासन) वाले देशों से समझा जा सकता है, जिनका वैचारिक आधार इन देशों में संप्रभुता ईश्वर, अल्लाह में अंतर्निहित मानी जाती है और कुरान व हदीस ही राज्य के सर्वोच्च कानून होते हैं। हां पारंपरिक इस्लामी न्यायशास्त्र फेकः (फेकाह) का जिम्मी सिद्धांत परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लागू होता है। इसके अंतर्गत गैरमुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने धर्म के प्रचार, नए पूजा स्थलों के निर्माण या राज्य के सर्वोच्च पदों, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से गैरइस्लामी धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध इसके चरम रूप को दर्शाता है। संवैधानिक रूप से इस्लामी किंतु मिश्रित मॉडल के उदाहरण हैं– पाकिस्तान, मलेशिया, मिस्र, जॉर्डन, जिनका वैचारिक आधार इस बात से परिलक्षित होता है किइन देशों के संविधान में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया है, किंतु साथ ही नागरिक संहिताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं का एक ढांचा भी मौजूद रहता है।यहां सिद्धांत और व्यवहार में एक स्थायी अंतर्विरोध दिखाई देता है। उदाहरण के लिएपाकिस्तान का संविधान अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त, ईशनिंदा कानून का दुरुपयोग वहां के हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों के विरुद्ध एक हथियार के रूप में होता है। मलेशिया में बुमीपुत्रा नीति के तहत मलय–मुसलमानों को आर्थिक और शैक्षणिक मोर्चे पर गैर–मुस्लिम चीनी और भारतीय अल्पसंख्यकों की तुलना में कानूनी वरीयता प्राप्त है। सैद्धांतिक पंथनिरपेक्ष मॉडल के उदाहरण हैं– तुर्की (ऐतिहासिक रूप से), अल्बेनिया, अजरबैजान, मध्य एशियाई देश (कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान)।सोवियत प्रभाव या मुस्तफा कमाल अतातुर्क जैसे सुधारकों के कारण इन देशों ने अपने संविधान को मजहब से अलग रखा।इन राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों को कानूनी रूप से समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। अजरबैजान या कजाकिस्तान में ईसाई और यहूदी अल्पसंख्यक अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। तथापि, वर्तमान समय में तुर्की जैसे देशों में पुनः इस्लामीकरण की प्रवृत्तियों के कारण ईसाई अल्पसंख्यकों (जैसे अर्मेनियाई और ग्रीक) के सांस्कृतिक अधिकारों पर अदृश्य दबाव बढ़ा है।लेकिन इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंताजनक आयाम जनसांख्यिकीय ह्रास का है। किसी भी समाज में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सबसे बड़ा प्रमाण उनकी जनसंख्या का स्थायित्व या वृद्धि होती है। मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के मुस्लिम बहुल देशों में अल्पसंख्यकों की संख्या में ऐतिहासिक गिरावट आई है।विभाजन के समय 1947 और उसके बाद के दशकों की तुलना में वर्तमान में इन देशों में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों का प्रतिशत निरंतर घटा है। इसका मुख्य कारण संस्थागत भेदभाव, जबरन धर्मांतरण और असुरक्षा जनित पलायन है।कभी इराक, सीरिया और लेबनान में ईसाई आबादी कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करती थी। किंतु इराक में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद और सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान आईएसआईएस जैसे कट्टरपंथी संगठनों के उदय ने यजीदी और ईसाई अल्पसंख्यकों का अभूतपूर्व उत्पीड़न किया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों ईसाइयों को अपनी प्राचीन मातृभूमि छोड़ने पर विवश होना पड़ा। वैश्विक मुस्लिमबहुल देशों के इस अंधकारमय परिदृश्य के बीच इंडोनेशिया एक विशिष्ट और मौलिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद इंडोनेशिया स्वयं को इस्लामी राष्ट्र घोषित नहीं करता।इंडोनेशियाई राज्य का मूलाधार पंचशील का सिद्धांत है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

ओडिशा में गणेश पूजा की धूम मंदिरों से शिक्षण संस्थानों तक उमड़े श्रद्धालु

भुवनेश्वर १४/०९ (संवाददाता): ओडिशा में गणेश पूजा का उत्साह देखने को मिला। राजधानी भुवनेश्वर से लेकर कटक और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की। मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक पंडालों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने विघ्नहर्ता गणेश से सुख-समृद्धि, ज्ञान, सफलता और परिवार की खुशहाली की कामना की। गणेश पूजा के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों और पूजा पंडालों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। लोगों ने भगवान गणेश को फूल, फल, मिठाई, दूर्वा और मोदक अर्पित किए। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान मंत्रोच्चार और गणपति बप्पा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। कई स्थानों पर सामूहिक आरती आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संज़्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया।

भुवनेश्वर में विभिन्न पूजा समितियों की ओर से आकर्षक पंडाल बनाए गए। पंडालों को रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों और सजावटी वस्तुओं से सजाया गया। भगवान गणेश की छोटी-बड़ी प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। शाम होते ही पंडालों की रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव की रौनक बढ़ा दी। परिवारों के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के दर्शन किए और पूजा समितियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कटक में भी गणेश पूजा को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। शहर के विभिन्न इलाकों में सामुदायिक पंडालों की स्थापना की गई और पारंपरिक तरीके से पूजा की गई। कई पंडालों में सुबह से शाम तक भक्ति गीत बजते रहे। पूजा समितियों ने श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की। स्थानीय युवाओं और स्वयंसेवकों ने भीड़ प्रबंधन और धार्मिक कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग किया। शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी गणेश पूजा श्रद्धा के साथ मनाई गई। गांवों में लोगों ने सामूहिक रूप से प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा-अर्चना की। कई स्थानों पर पारंपरिक संगीत, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों और युवाओं ने उत्साह से इन कार्यक्रमों में भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में पूजा पंडाल सामाजिक मेल-जोल और सामुदायिक एकता के केंद्र भी बने।

गणेश पूजा का शिक्षण संस्थानों में विशेष महत्व दिखाई दिया। भगवान गणेश को ज्ञान, विवेक और बुद्धि का देवता माना जाता है। इसी कारण स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक

परिसरों में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने श्रद्धा के साथ पूजा की। कई संस्थानों में गणेश प्रतिमा स्थापित कर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। छात्रों ने पढ़ाई में सफलता, बेहतर परीक्षा परिणाम और उज्ज्वल भविष्य के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद मांगा। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों को इस पर्व के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताया। पूजा के बाद प्रसाद बांटा गया और कई संस्थानों में नृत्य, संगीत, भाषण तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं।

कई विद्यार्थियों ने पूजा की तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभाई। किसी ने पंडाल की सजावट की तो किसी ने फूलों और पूजा सामग्री की व्यवस्था संभाली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। कुछ संस्थानों में चित्रकला, रंगोली और भक्ति गीत प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को धार्मिक परंपराओं के साथ सामूहिक जिज़्मेदारी और सहयोग का संदेश दिया गया। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है ज़्योंकि मान्यता है कि उनकी आराधना से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इसी कारण व्यापारियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों सहित हर वर्ग के श्रद्धालुओं ने पूजा कर सफलता और समृद्धि की कामना की। पूजा पंडालों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी प्रमुखता से देखने को मिला। कई आयोजकों ने सजावट के लिए प्राकृतिक और दोबारा इस्तेमाल की जा सकने वाली सामग्री को प्राथमिकता दी। श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक का कम उपयोग करने की अपील की गई। पूजा स्थलों के आसपास साफ-सफाई के लिए स्वयंसेवकों की टीमें भी सक्रिय रहीं। त्योहार को लेकर बाजारों में भी रौनक बनी रही। फूलों, फलों, मिठाइयों, पूजा सामग्री और सजावट की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। भगवान गणेश को प्रिय माने जाने वाले मोदक और लड्डू की मांग अधिक रही। मूर्तिकारों और सजावटी सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को भी पूजा के कारण कारोबार बढ़ने की उज़्मीद रही। शाम के समय कई पूजा पंडालों में भजन संध्या और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों और विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कुछ जगह धार्मिक कथाओं और भगवान गणेश से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव, शिक्षा और नैतिक मूल्यों का संदेश दिया गया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं में आस्था और उल्लास का अनूठा संगम दिखाई दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भगवान गणेश के जयकारों और भक्ति गीतों से मंदिर तथा पंडाल गूंजते रहे। ओडिशा में मनाई गई गणेश पूजा ने धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश दिया। भुवनेश्वर तथा कटक के भव्य पंडालों से लेकर ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक आयोजनों तक उत्सव का रंग छाया रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश से सभी बाधाओं को दूर करने और जीवन में ज्ञान, शांति, सुख तथा सफलता प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस्पात शहर में हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी का पालन

राउरकेला १४/०९ (संवाददाता):इस्पात शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संगठनों में 14 सितंबर, 2026 को गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ पालन किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी (डी.आई.सी.), श्री आलोक वर्मा ने सेज़्टर-18 स्थित दीपिका इस्पात शिक्षा सदन में आयोजित पूजा समारोह में भाग लिया तथा भगवान विनायक को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके साथ दीपिका महिला संघति की अध्यक्षा, श्रीमती नम्रता वर्मा, कार्यपालक निदेशक (माइंस डेवलपमेंट-सी.एम.एल.ओ.), श्री बी.के.गिरि, कार्यपालक निदेशक (वर्क्स), श्री बिस्वरंजन पलई, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक (माइंस), श्री एम.पी.सिंह, कार्यपालक निदेशक (परियोजना), श्री एस.पालचौधरी, डी.एम.एस. की सभी उपाध्यक्षा, श्रीमती स्मिता गिरि, डॉ. प्रतिज्ञा पलई,

श्रीमती रीता रानी, श्रीमती नबनीता पालचौधरी, एवं संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इसी प्रकार सेज़्टर-5 स्थित बिगिनर्स अकादमी में भी दीपिका महिला संघति की अध्यक्षा, उपाध्यक्षा एवं शासी निकाय के सदस्यों द्वारा गणेश पूजा की गई। इस्पात शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी गणेश पूजा उत्साह एवं उमंग के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी संज़्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उल्लेखनीय है कि हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद मास के शुज़्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मदिवस के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यह भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। पारंपरिक कारीगरों द्वारा गणेश प्रतिमाओं का निर्माण त्योहार से कई महीने पहले ही शुरू कर दिया जाता है। इन प्रतिमाओं को घरों में सुसज्जित वेदियों तथा भव्य रूप से सजाए गए सार्वजनिक पंडालों में विधि-विधान एवं समारोहपूर्वक स्थापित किया जाता है।

नुआखाई पर्व पर सीएम मोहन माझी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

भुवनेश्वर १४/०९ (संवाददाता): मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को ओडिशा के लोगों को राज्य के सबसे बड़े कृषि त्योहार %नुआखाई% की बधाई दी, जो कल मनाया जाएगा। एक वीडियो संदेश में मुज़्यमंत्री ने कहा, मैं राज्य के सभी लोगों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नुआखाई सिर्फ़ एक त्योहार नहीं है; यह हमारी मिट्टी, संस्कृति, जीवन शैली और सामाजिक एकता की धड़कन है। उन्होंने कहा, इस खुशी के त्योहार के दौरान, सभी मतभेदों, कड़वाहट और अहंकार को भुलाकर हम अपने बड़ों को सज़्मानपूर्वक प्रणाम (जुहार) करते हैं और वे छोटों पर प्यार और आशीर्वाद बरसाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह सुंदर परंपरा हमारे परिवार, समाज और भाईचारे के बंधन को और मजबूत करती है। उन्होंने कहा, इस शुभ दिन पर, मैं सभी से—छात्रों, युवाओं, श्रमिकों, किसानों और सैनिकों से—आग्रह करता हूं कि वे 2036 तक समृद्ध ओडिशा और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुज़्यमंत्री ने कामना की, नुआखाई सभी के जीवन में नई उज़्मीद लाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि मां समलेई सभी के जीवन को खुशी, शांति, प्रगति और सफलता से भर दें। एक बार फिर, सभी को मेरी ओर से नुआखाई जुहार (बधाई)। जय मां समलेई।

बीजेडी ने सीएम माझी की यूएई यात्रा के प्रचार की आलोचना की

भुवनेश्वर १४/०९ (संवाददाता): बीजेडी ने गुरुवार को राज्य सरकार की आलोचना करते हुए मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी की UAE यात्रा के बहुत ज़्यादा प्रचार पर सवाल उठाए और इस यात्रा से मिले विदेशी निवेश का पूरा ज़्यौरा मांगा। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJD प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने कहा कि हालांकि रोज़ाना के अख़बारों के पहले पन्नों पर बड़े-बड़े विज्ञापनों के ज़रिए इस यात्रा का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन इसके असल नतीजों और परिणामों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। मोहंती ने कहा कि ष्टरू की यात्रा के दौरान ओडिशा में 11.5 अरब डॉलर का इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड एल्युमीनियम प्रोजेज़्ट शुरू करने के लिए अडानी ग्रुप और द्व।ष्ट के साथ एक रूश्व पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि ठीक यही रूश्व भुवनेश्वर में एक प्रोजेज़्ट विकसित करने के लिए अडानी ग्रुप-द्व।ष्ट जॉइंट वेंचर के साथ सिर्फ़ दो महीने पहले साइन किया गया था। मोहंती ने कहा कि हालांकि सरकार ने बार-बार दावा किया है कि उसने ओडिशा में 20 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश आकर्षित किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर असल काम सीमित ही रहा है। उन्होंने कहा, सिर्फ़ लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव ही असल रूप ले पाए हैं, जबकि राज्य में लगभग 50 छोटे और मध्यम उद्योगों ने अपनी शुरुआती प्रक्रियाएं शुरू की हैं।

आरएसपी की हॉट स्ट्रिप मिल-2 द्वारा स्मार्ट उत्पाद मिश्रण के माध्यम से वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देती है

राउरकेला १४/०९ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) का अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल-2 (एच.एस.एम.-2), जो हॉट रोल्ड (एच.आर.) क्वायल एवं एच.आर. शीट का उत्पादन करता है, ने अगस्त 2026 के दौरान वैल्यू-एडेड और स्पेशल-ग्रेड स्टील के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है।

वर्तमान बाजार मांग के अनुरूप अपनी उत्पादन रणनीति को संयोजित करते हुए तथा सेल के व्यापक स्मार्ट एवं मूल्य-उन्मुख उत्पाद मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एच.एस.एम.-2 ने अगस्त माह के दौरान कम मोटाई वाले सेज़्शन एवं विशेष ग्रेड के इस्पात के उत्पादन पर विशेष जोर दिया। मिल ने 2 मि.मी. एवं उससे कम मोटाई के एच.आर. क्वाएयल की 843 क्वाइयल, कुल 16,395 टन, का उत्पादन किया। इससे कम

गेज वाले उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ बिक्री से प्राप्ति में वृद्धि करने में भी मदद मिली।

विशेष इस्पात खंड में, एक समर्पित अभियान के दौरान एच.एस.एम.-2 ने 15.9 मि.मी. मोटाई के क्व्ह्र ङ्क70 क्कस्र2 ग्रेड इस्पात की 61 क्वा-यल सफलतापूर्वक रोल कीं, जिनकी कुल मात्रा लगभग 1,770 टन रही। यह उपलज़्धि बदलती ग्राहक एवं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च-मूल्य तथा कठोर गुणवज़ा मानकों वाले उत्पादों के उत्पादन की मिल की क्षमता को रेखांकित करती है। क म मोटाई वाले सेज़्शन एवं विशेष ग्रेड पर रणनीतिक फोकस से बेहतर उत्पाद प्राप्ति एवं मूल्यवर्धन के माध्यम से संयंत्र के लाभप्रदता में सकारात्मक योगदान की अपेक्षा है। यह पहल बाजार की बदलती परिस्थितियों के प्रति आर.एस.पी. की तत्परता को भी दर्शाती है तथा सेल की व्यापक व्यावसायिक रणनीति के अनुरूप उत्पादन को सुनिश्चित करती है। इसी क्रम में, एच.एस.एम.-2 ने नियमित रूप से विभिन्न अन्य ग्रेड एवं मोटाई के इस्पात का उत्पादन भी जारी रखा है। यह उत्पादन ग्राहक आदेशों एवं बाजार की आवश्यकताओं से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिससे संतुलित एवं ग्राहक-केंद्रित उत्पाद पोर्टफोलियो बनाए रखने में सहायता मिल रही है।

इस उपलज़्धि में एक और महत्वपूर्ण उपलज़्धि जुड़ गई है। मिल ने एच.आर. क्वाजयल एवं एच.आर. प्लेट, दोनों में अगस्त माह का अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है, जो इसके परिचालन प्रदर्शन में एक और महत्वपूर्ण उपलज़्धाि है।

एच.एस.एम.-2 की ये उपलज़्धियाँ परिचालन उत्कृष्टता, उत्पाद विविधता एवं बाजार की आवश्यकताओं के प्रति तत्परता को एक साथ समाहित करने की मिल की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। इससे मूल्य प्राप्ति को अधिकतम करने तथा समग्र व्यावसायिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के आर.एस.पी. के प्रयासों को और मजबूती मिली है।